संकल्प पत्र 2024

जम्मू-कश्मीर

विधानसभा चुनाव

भारतीय जनता पार्टी, जम्मू-कश्मीर

“

विकसित जम्मू-कश्मीर बनाने के लिए सरकार का ध्यान गरीबों, किसानों, युवाओं और नारी शक्ति के विकास पर केंद्रित है।

”

- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी

घोषणापत्र
समिति के सदस्य

प्रमुख
डॉ निर्मल सिंह

सह-प्रमुख

- एड. सुनील सेठी
- डॉ. द्रक्षण अंद्राबी
- देवेंद्र सिंह राणा
- एड. आर.एस पठानिया
- एड. अभिनव शर्मा
- जी.एल. रैना
- सुरिंदर अंबरदार
- जावेद कक्रू
- फारूक रेशी (रिटड. एस.पी)
- नियाज़ अंद्राबी

विषय-सूची

- जम्मू-कश्मीर में भाजपा की प्रमुख उपलब्धियाँ
- नए जम्मू-कश्मीर के लिए भाजपा के 25 संकल्प
- जम्मू और कश्मीर के लिए एक समग्र दृष्टिकोण
- जम्मू क्षेत्र के संघर्षों को मान्यता: तीव्र गति से विकास के लिए ठोस प्रयास

01 सुरक्षा- आतंक मुक्त जम्मू और कश्मीर

02 युवा सशक्तिकरण और खेल विकास

03 नारी शक्ति- महिलाओं का सशक्तिकरण और उनके अधिकारों की रक्षा

04 कृषि, किसान कल्याण और पशुपालन

05 गरीब कल्याण- सशक्त और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण

06 संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा

07 जम्मू-कश्मीर- पर्यटन का मुकुट रत्न

08 संस्कृति और सभ्यता

09 आर्थिक सशक्तिकरण और औद्योगिक विकास

10 शिक्षा और कौशल विकास

11 सुशासन- विकास और समृद्धि का शासन

12 जम्मू और कश्मीर का निर्माण- बुनियादी ढांचे का विकास और कनेक्टिविटी का विस्तार

13 कश्मीरी पंडितों का कल्याण

14 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन

जम्मू-कश्मीर में भाजपा की प्रमुख उपलब्धियाँ

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और मोदी सरकार के मजबूत हस्तक्षेप के माध्यम से, अब जम्मू-कश्मीर में शांति और समृद्धि बहाल हुई और आतंकवादी हमलों, सीमा-पार गोलीबारी और उग्रवाद में स्पष्ट कमी आई है। 2019 के बाद, जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमलों में 75% की कमी आई है और 2022 से कोई पत्थरबाजी या संगठित हड़ताल दर्ज नहीं की गई है।

अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से जम्मू-कश्मीर का भारत के संविधान के साथ पूर्ण एकीकरण हो गया है। इससे पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना संभव हुई और प्रमुख केंद्रीय कानून अब यहाँ लागू हुए है जिससे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिला है।

मोदी सरकार ने महिलाओं को मालिकाना हक की गारंटी दी है। महिलाओं को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब जम्मू-कश्मीर में घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम, पोक्सो अधिनियम जैसे कई महिला-केंद्रित कानून लागू हैं।

पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को पूर्ण नागरिकता अधिकार प्राप्त हुए, जिससे दशकों से चले आ रहे दमनकारी व्यवहार का अंत हुआ। जम्मू-कश्मीर में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करके सामाजिक न्याय प्रदान भी सुनिश्चित किया गया है।

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023 को अधिनियमित किया गया, जिसमें जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सभी निर्वाचित सीटों में से एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गईं, जो महिला अधिकारों और कल्याण के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

चिनाब रेलवे ब्रिज (लागत ₹ 14,000 करोड़), बनिहाल काजीगुंड रोड टनल (लागत ₹ 3100 करोड़) और दिल्ली-कटरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे (लागत ₹ 40,000 करोड़) सहित कई परियोजनाओं ने जम्मू और कश्मीर के बुनियादी ढांचे के परिदृश्य को बदल दिया है।

भारत की दूसरी वंदे भारत ट्रेन दिल्ली और कटरा के बीच शुरू की गई। इसके अलावा, लोगों को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए उसी मार्ग पर एक और वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई।

मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए 'अरोमा मिशन' के तहत लैवेंडर की खेती जैसी पहल के कारण किसानों की आय में वृद्धि हुई।

जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा अधिनियम, 2020 ने कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी।

जम्मू-कश्मीर में भाजपा की प्रमुख उपलब्धियाँ

ज़ोजिला सुरंग का निर्माण ₹6,809 करोड़ की लागत से किया गया, जिससे श्रीनगर और लद्दाख के बीच सभी मौसम में संपर्क सुनिश्चित हुआ।

जम्मू और श्रीनगर मेट्रोलाइट परियोजनाएं क्रमशः ₹ 4,352 करोड़ और ₹ 3,590 करोड़ की लागत से 2026 तक निवासियों और पर्यटकों को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार हो जाएंगे।

जम्मू-कश्मीर औद्योगिक नीति 2021-30, जम्मू-कश्मीर पर्यटन नीति 2020 और जम्मू-कश्मीर स्टार्ट-अप नीति 2024-27 जैसी नई नीतियों से जम्मू-कश्मीर में उद्योगिक निवेश और विकास बढ़ा है।

अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर को ₹80,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है।

जम्मू-कश्मीर में किसानों का जीवन बेहतर बनाने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12.68 लाख पात्र किसानों को ₹3,000 करोड़ से अधिक की धनराशि दी गई।

किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 17 मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) के साथ एकीकृत किया गया है तथा 51,748 से अधिक किसानों, व्यापारियों और एफपीओ को पंजीकृत किया गया है।

हमने अवंतीपुरा और विजयपुर में एम्स के साथ-साथ जम्मू में क्षेत्र का सबसे पहला आईआईएम, आईआईटी की स्थापना करके जम्मू-कश्मीर के युवाओं को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान की।

जम्मू और कश्मीर ने 2023 में रिकॉर्ड 2.11 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित किया, जिससे जम्मू और कश्मीर प्रभावी रूप से आतंकवाद की राजधानी से पर्यटन की राजधानी में परिवर्तित हो गया है।

गरीबों के लिए किफायती आवास सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के अंतर्गत 3.40 लाख मकान स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 2.10 लाख मकान पूरे हो चुके हैं।

श्रीनगर में पहली फार्मूला 4 रेसिंग प्रतियोगिता और श्रीनगर मैराथन जम्मू-कश्मीर में आए सकारात्मक बदलावों को दुनिया के सामने रखते हैं।

सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केसर, बसोहली चित्रकारी, कलाडी कुल्चा, राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट आदि को जीआई टैग प्रदान किए गए हैं।

नए जम्मू-कश्मीर के लिए भाजपा के 25 संकल्प

01

हम आतंकवाद और अलगाववाद का पूर्णतः सफाया करके जम्मू-कश्मीर को विकास और प्रगति में देश में सबसे अग्रणी बनायेंगे।

02

जम्मू और कश्मीर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण अनुसार महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए, हम महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा व आत्मनिर्भरता को बढ़ाएंगे और उन्हें प्राथमिकता देंगे:

- 'माँ सम्मान योजना' के कार्यान्वयन के माध्यम से हम जम्मू और कश्मीर के हर घर की सबसे वरिष्ठ महिला को प्रति वर्ष ₹ 18,000 प्रदान करेंगे
- महिला स्वयं सहायता समूहों के बैंक ऋण पर ब्याज के विषय पर राज्य सरकार सहायता करेगी
- हम उज्ज्वला लाभार्थियों को हर साल 2 मुफ्त एल.पी.जी सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे।

03

पंडित प्रेम नाथ डोगरा रोजगार योजना (PPNDRY) के माध्यम से हम जम्मू और कश्मीर में 5 लाख रोज़गार के अवसर पैदा करेंगे।

04

हम 'प्रगति शिक्षा योजना' के अंतर्गत कॉलेज के विद्यार्थियों को यातायात-संबंधी भत्ते के रूप में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से प्रति वर्ष ₹3,000 प्रदान करेंगे।

05

हम जम्मू और कश्मीर के युवाओं को JKPSC और UPSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सक्षम बनाएंगे, इसके लिए हम:

- समय पर साक्षात्कार के साथ निष्पक्ष और न्यायपूर्ण भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे
- 2 वर्षों के लिए ₹ 10,000 तक की कोचिंग फीस की प्रतिपूर्ति प्रदान करेंगे
- परीक्षा केन्द्रों तक यातायात-संबंधी लागत और एकमुश्त आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति करेंगे।

नए जम्मू-कश्मीर के लिए भाजपा के 25 संकल्प

06

हम दूरदराज के क्षेत्रों में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को टैबलेट/लैपटॉप प्रदान करेंगे।

07

हम जम्मू-कश्मीर में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे और विकसित करेंगे, जिसमें निम्नलिखित पर विशेष जोर दिया जाएगा:

- जम्मू क्षेत्र की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकारी योजनाओं और शिल्प कार्यक्रमों की परिपूर्णता की निगरानी करने के लिए तीन क्षेत्रीय विकास बोर्ड की स्थापना
- डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी, पुंछ और उधमपुर और कठुआ के ऊपरी क्षेत्रों में पर्यटन उद्योग
- श्रीनगर शहर की डल झील को विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे, और जल क्रीड़ा (Water Sports) को बढ़ावा देंगे
- श्रीनगर के टटू ग्राउंड में मनोरंजन पार्क (Amusement Park) स्थापना
- जम्मू शहर में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के रूप में आईटी हब की स्थापना
- कश्मीर घाटी में गुलमर्ग और पहलगाम को आधुनिक पर्यटन शहर के रूप में विकसित करेंगे और इसके लिए जरूरी बुनियादी ढांचे को बढ़ाएंगे
- उधमपुर में फार्मास्युटिकल पार्क और किश्तवाड़ में आयुष हर्बल पार्क की स्थापना
- गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट के समान तवी रिवरफ्रंट का विकास
- रंजीत सागर बांध के लिए एक अलग झील विकास प्राधिकरण बना पर्यटन को बढ़ावा।

08

मौजूदा व्यवसायों और छोटे व्यापारियों को समर्थन देने के लिए निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे:

- जम्मू-कश्मीर में 7,000 मौजूदा एमएसएमई (MSME) इकाइयों की मौजूदा समस्याओं के समाधान के लिए एक नई नीति तैयार की जाएगी ताकि भूमि और सार्वजनिक उपयोगिताओं तक पहुंच को संबोधित किया जा सके
- वर्तमान बाजारों और वाणिज्यिक स्थानों पर काम कर रहे छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के पट्टा विलेखों (Lease Deeds) के नियमितीकरण से संबंधित मुद्दों को समयबद्ध तरीके से निपटाया जाएगा
- इसके साथ ही इकाइयों और मजदूरों की समस्याओं का निवारण करने के लिए हम कठोर कदम उठाएंगे।

नए जम्मू-कश्मीर के लिए भाजपा के 25 संकल्प

09

हम अटल आवास योजना के माध्यम से भूमिहीन लाभार्थियों के लिए 5 मरला ज़मीन का मुफ्त आवंटन सुनिश्चित करेंगे।

10

हम जम्मू कश्मीर में उपयोगिताओं और अन्य सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान निम्नलिखित माध्यम से करेंगे:

- हम सभी उपभोक्ताओं के लिए बिजली और पानी के बकाया बिलों के लिए एक समाधान योजना लाएंगे
- हम 'हर घर नल से जल' के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराएंगे
- हम प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से परिवारों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएंगे, जिसमें सौर उपकरण की स्थापना के लिए ₹10,000 की सब्सिडी भी दी जाएगी।

11

हम वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता पेंशन को ₹1,000 से तीन-गुना बढ़ाकर ₹3,000 करेंगे, जिससे कमजोर वर्गों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित हो सके।

12

हम सभी के लिए सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए आयुष्मान भारत सेहत योजना के ₹5 लाख कवरेज के अतिरिक्त ₹2 लाख प्रदान करेंगे।

13

हम मौजूदा और आगामी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से 1,000 नई सीटें जोड़ेंगे।

14

हम पीएम किसान सम्मान निधि के तहत ₹10,000 प्रदान करेंगे, जिसमें मौजूदा ₹6,000 के साथ अतिरिक्त ₹4,000 शामिल होंगे, जिससे जम्मू और कश्मीर में किसानों की उन्नति सुनिश्चित होगी।

नए जम्मू-कश्मीर के लिए भाजपा के 25 संकल्प

15

हम कृषि गतिविधियों के लिए बिजली की दरों को 50% तक कम करेंगे, जिससे किसानों के लिए सिंचाई पंप और अन्य मशीनरी संचालित करना आसान हो जाएगा।

16

हम सरकारी कर्मचारियों के लिए सुधार लागू करेंगे जिससे:

- सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित होगा
- सभी कर्मचारियों, विशेषकर कश्मीर घाटी में कार्यरत अनुसूचित जाति एवं अन्य कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति बनाई जाएगी।

17

हम अग्निवीरों को जम्मू-कश्मीर की सरकारी नौकरियों और पुलिस भर्ती में 20% कोटा देंगे, और सामान्य कोटे पर कोई प्रभाव डाले बिना जम्मू-कश्मीर की आरक्षण नीति का पालन करेंगे।

18

हम एडहॉक/संविदा/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करेंगे। हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, एनएचएम कार्यकर्ताओं, रहबर-ए-खेल कर्मचारियों (ReK), सामुदायिक सूचना केंद्र (CIC) संचालकों, होम गार्ड और राष्ट्रीय युवा कोर (NYC) जैसे महत्वपूर्ण सामुदायिक कार्यकर्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए लक्षित अतिरिक्त सहायता प्रदान करेंगे।

19

हम 10,000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कों का निर्माण कर सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी गांव पीछे न छूटें। इसके साथ ही हम जम्मू-कश्मीर में निर्बाध कनेक्टिविटी के लिए 'हर सुरंग तेज़ पहल' योजना के अंतर्गत साधना पास सुरंग, कटरा-बनिहाल रेलवे सुरंग जैसी परियोजनाओं को पूरा करेंगे।

20

हम शहरी संपर्क में सुधार और गतिशीलता बढ़ाने के लिए जम्मू और श्रीनगर में मेट्रो सेवाएं जल्दी शुरू करेंगे।

नए जम्मू-कश्मीर के लिए भाजपा के 25 संकल्प

21

हम ऋषि कश्यप तीर्थ पुनरुद्धार अभियान के अंतर्गत हिंदू मंदिरों और धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण करेंगे। हम 100 खंडहर मंदिरों का जीर्णोद्धार करेंगे और मौजूदा मंदिरों का और अधिक विकास करेंगे धार्मिक और आध्यात्मिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी से, जिसमें शंकराचार्य मंदिर (ज्येष्ठेश्वर मंदिर), रघुनाथ मंदिर और मार्तंड सूर्य मंदिर शामिल है।

22

हम जम्मू-कश्मीर में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी बस्तियों से निपटने के लिए सख्त अभियान चलाएंगे।

23

कश्मीरी पंडित समुदाय की सुरक्षित वापसी और पुनर्वास में तेजी लाने और उसे सुनिश्चित करने के लिए, हम टीका लाल टपलू विस्थापित समाज पुनर्वास योजना (TLTVSPY) शुरू करेंगे। हम पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों, पीओजेके शरणार्थियों और वाल्मीकि, गोरखा जैसे आंतरिक रूप से उपेक्षित समुदायों के पुनर्वास में भी तेजी लाएंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू संभाग के विस्थापित लोगों को वे सभी उचित लाभ, सुरक्षा और संरक्षण प्राप्त हों जो कश्मीरी विस्थापितों को मिलती हैं।

24

हम एक श्वेत पत्र प्रकाशित करेंगे और आतंकवाद के सभी पीड़ितों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे, जिसके लिए हम:

- कोर्ट में मामलों को फास्ट ट्रैक करेंगे
- पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे
- राज्य में विधि का शासन सुनिश्चित करेंगे।

25

हम पिछले वर्षों के विपरीत स्वतंत्र और निष्पक्ष जनगणना करेंगे, जिससे उचित निर्णय लेने, समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करने तथा कमज़ोर समुदायों के लिए लक्षित हस्तक्षेप सुनिश्चित होगा।

जम्मू-कश्मीर के लिए
एक समग्र दृष्टिकोण

जम्मू और कश्मीर अपने इतिहास के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। "एक विधान, एक निशान, एक प्रधान" के लिए वर्षों के संघर्ष और बलिदान के बाद, हमने जम्मू और कश्मीर को भारत के साथ पूरी तरह से एकीकृत किया है। इस ऐतिहासिक कदम से यहाँ सुनिश्चित हुआ कि भारतीय संविधान अब बिना किसी संशोधन के जम्मू-कश्मीर पर लागू होगा और इसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी सही ठहराया है। आज अलगाव, भेदभाव और शोषण की बाधाओं को जम्मू-कश्मीर में ध्वस्त कर दिया गया है।

नई जनकल्याणकारी पहलों के माध्यम से सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन हो रहा है। आतंकवाद, अलगाववाद और भाई-भतीजावाद की समस्याओं का दृढ़ता से समाधान किया गया है, जिससे जाति, पंथ, धर्म, क्षेत्र या लिंग के भेदभाव के बिना सभी नागरिकों के लिए शांति, विकास, और विश्वास सुनिश्चित हो सके।

लेकिन पुरानी व्यवस्था से लाभ उठाने वाली ताकतें असहज हैं और इन बदलावों को पलटना चाहती हैं। कश्मीर केंद्रित इन वंशवादी राजनीतिक संगठनों ने क्षेत्र, धर्म, जाति और पंथ के विभाजन का फायदा उठाकर लोगों को गुमराह करने के लिए पक्षपातपूर्ण बयानबाजी भी शुरू कर दी हैं।

कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, और पीडीपी जैसे मुख्यधारा के राजनीतिक दलों ने लंबे समय से धोखे की राजनीति की है और वे आम जनता की पीड़ा और अभाव के लिए जिम्मेदार हैं। कभी-कभी वे "मुन् तु शुदम तु मुन् शुदी, मुन् तुन् शुदम तु जान शुदी" जैसी काव्य घोषणाओं के साथ एकता की बात करते हैं। लेकिन, उन्होंने भारत के हितों के विरोधी ताकतों के साथ सहयोग करते हुए कुशासन और भ्रष्टाचार के माध्यम से नागरिकों को अलग-थलग कर दिया है। एकता के अपने दावों के बावजूद, ये दल अक्सर एक-दूसरे के साथ विश्वासघात करते हैं, फिर भी सत्ता के लिए समझौता करते हैं, और एक बार फिर जम्मू और कश्मीर के लोगों का शोषण करने की कोशिश कर रहे हैं।

एक पार्टी के रूप में जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा, हम आर्थिक विकास, सामाजिक उत्थान और बुनियादी ढांचे की प्रगति के माध्यम से जम्मू और कश्मीर को सशक्त बनाने के लिए एक योजना प्रस्तुत करते हैं, जिसमें एक ऐसे क्षेत्र की कल्पना करते हैं जहां प्रत्येक नागरिक समृद्ध हो और हमारी समृद्ध विरासत का जश्न मनाया जाए।

विकसित भारत के लिए विकसित जम्मू-कश्मीर का निर्माण हमारा संकल्प है।

भारत माता की जय!

जम्मू क्षेत्र के संघर्षों को मान्यता:

तीव्र गति से विकास के लिए ठोस प्रयास

जम्मू क्षेत्र को लम्बे समय तक हिंसा और आतंकवाद का दंश झेलना पड़ा है, जिसके कारण लोगों के जीवन, स्वतंत्रता और आजीविका के अधिकार प्रभावित हुए हैं। इसलिए निम्नलिखित संकल्पों के माध्यम से क्षेत्र के विकास को तेजी से आगे बढ़ाना आवश्यक है:

- हम जम्मू में तीन क्षेत्रीय विकास बोर्ड स्थापित करेंगे, जो यह निगरानी करेंगे कि जम्मू क्षेत्र के जिलों की आकांक्षाओं का विकास उनकी शक्तियों और भविष्य की जरूरतों के आधार पर स्थानीय समुदाय की भागीदारी से हो।
- ये क्षेत्रीय विकास बोर्ड:
  - पूर्व-निर्धारित नियमों के आधार पर अपने क्षेत्र के विकास के वर्तमान स्तर का आकलन करेंगे
  - संघ और राज्य स्तरीय योजनाओं की संतृप्ति सहित विकास के लिए एक कार्य योजना देंगे
  - कार्य योजना को साकार करने के लिए कार्मिक और व्यय के संदर्भ में प्रयास का अनुमान लगाएंगे
  - विकास प्रयासों की प्रगति और प्रभाव का आकलन करेंगे।
- हम जम्मू संभाग में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे और इसका विकास करेंगे, जिसमें हम इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देंगे:
  - डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी, पुंछ और उधमपुर और कठुआ के ऊपरी क्षेत्रों में पर्यटन उद्योग
  - अंतराष्ट्रीय बॉर्डर और नियंत्रण रेखा पर बॉर्डर पयर्टन
  - जम्मू शहर में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के रूप में आईटी हब की स्थापना
  - उधमपुर में फार्मास्युटिकल पार्क और किश्तवाड़ में आयुष हर्बल पार्क की स्थापना।

- रियासी जिले के सलाल-हैमना क्षेत्र में हाल ही में खोजे गए 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार के सुरक्षित और टिकाऊ खनन में तेजी लाएंगे तथा जिला खनिज निधि में अर्जित रॉयल्टी का लाभ क्षेत्र के विकास के लिए करेंगे।

- गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर जम्मू शहर के बीच में तवी रिवर फ्रंट का विकास किया जाएगा, ताकि इसमें सैर-सपाटे और पैदल चलने वालों के लिए जगह, पार्क, खुली हवा में फिटनेस सेंटर, खेल सुविधाएं और जैव विविधता पार्क शामिल हों। सभी अपशिष्ट और अन्य डिस्चार्ज को डिस्चार्ज करने से पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में उपचारित किया जाएगा।

- हम संपर्क बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जम्मू में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित करने का आग्रह करेंगे।

- हम स्कुअस्त (SKUAST) विश्वविद्यालय, जम्मू का नाम बदलकर बाबा जित्तो कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रखेंगे तथा इसे केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में अपग्रेड करेंगे, जिससे जम्मू-कश्मीर में युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित होगी।

- हम जम्मू हवाई अड्डे पर कार्गो हैंडलिंग क्षमता का नवीनीकरण और विस्तार करेंगे।

- हम प्रमाणिक जानकारी प्रसारित करने और स्थानीय संस्कृतियों को संरक्षित करने के लिए आकाशवाणी और डीडी केंद्र जम्मू को उचित व्यवस्था और उपकरणों के साथ उन्नत करना सुनिश्चित करेंगे।

- हम जम्मू शहर में भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) परिसर की स्थापना करेंगे।

- जम्मू क्षेत्र की सांस्कृतिक और सभ्यतागत प्रकृति सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, इसके लिए हम:

  - धार्मिक आध्यात्मिक सर्किट बनाएँगे और वैष्णो देवी तीर्थस्थल, रघुनाथ मंदिर, पीर खो गुफा मंदिर, शिवखोरी और मचैल माता मंदिर में आधुनिक सुविधाओं का विकास सुनिश्चित करेंगे

  - बसोहली पेंटिंग जैसे पारंपरिक कला रूपों को बाजार में उतारेंगे, जिन्हें हाल ही में मार्च 2023 में भौगोलिक संकेत टैग (GI Tag) प्राप्त हुआ है

  - दीपावली, लोहड़ी, महाशिवरात्रि, बसंत पंचमी जैसे लोकप्रिय हिंदू त्योहारों के अलावा, हम स्थानीय त्योहारों के आयोजन में भी सहायता प्रदान करेंगे, जैसे कि सांबा में आठ दिवसीय रथ खड़ा मेला, कार्तिक पूर्णिमा से पहले पंज भीखम (भीष्म पंचक) के रूप में तुलसी पूजा की पांच दिवसीय अवधि का उत्सव।

सुरक्षा-

आतंक मुक्त

जम्मू और कश्मीर

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति (Zero Tolerance Policy) का पालन किया है और जम्मू-कश्मीर में शांति एवं स्थिरता की स्थापना की है। इससे संगठित पत्थरबाजी की घटनाएं और संगठित हड़तालें, जो 2018 में क्रमशः 1,328 और 52 थीं, 2023 तक घटकर "0" हो गई हैं।

भाजपा यह सुनिश्चित करेगी कि:

- हम आतंकवाद और अलगाववाद का पूर्णतः सफाया करके जम्मू-कश्मीर को विकास और प्रगति में देश में सबसे अग्रणी बनायेंगे।

- हम एक श्वेत पत्र प्रकाशित करेंगे और आतंकवाद के सभी पीड़ितों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे, जिसके लिए हम:
  - कोर्ट में मामलों को फास्ट ट्रैक करेंगे
  - पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे
  - राज्य में विधि का शासन सुनिश्चित करेंगे।

- हम जम्मू-कश्मीर में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी बस्तियों से निपटने के लिए सख्त अभियान चलाएंगे।

- हम उन्नत निगरानी, खुफिया जानकारी, और मजबूत सैन्य एवं अर्धसैन्य बलों की उपस्थिति से 'आतंक-मुक्त जम्मू और

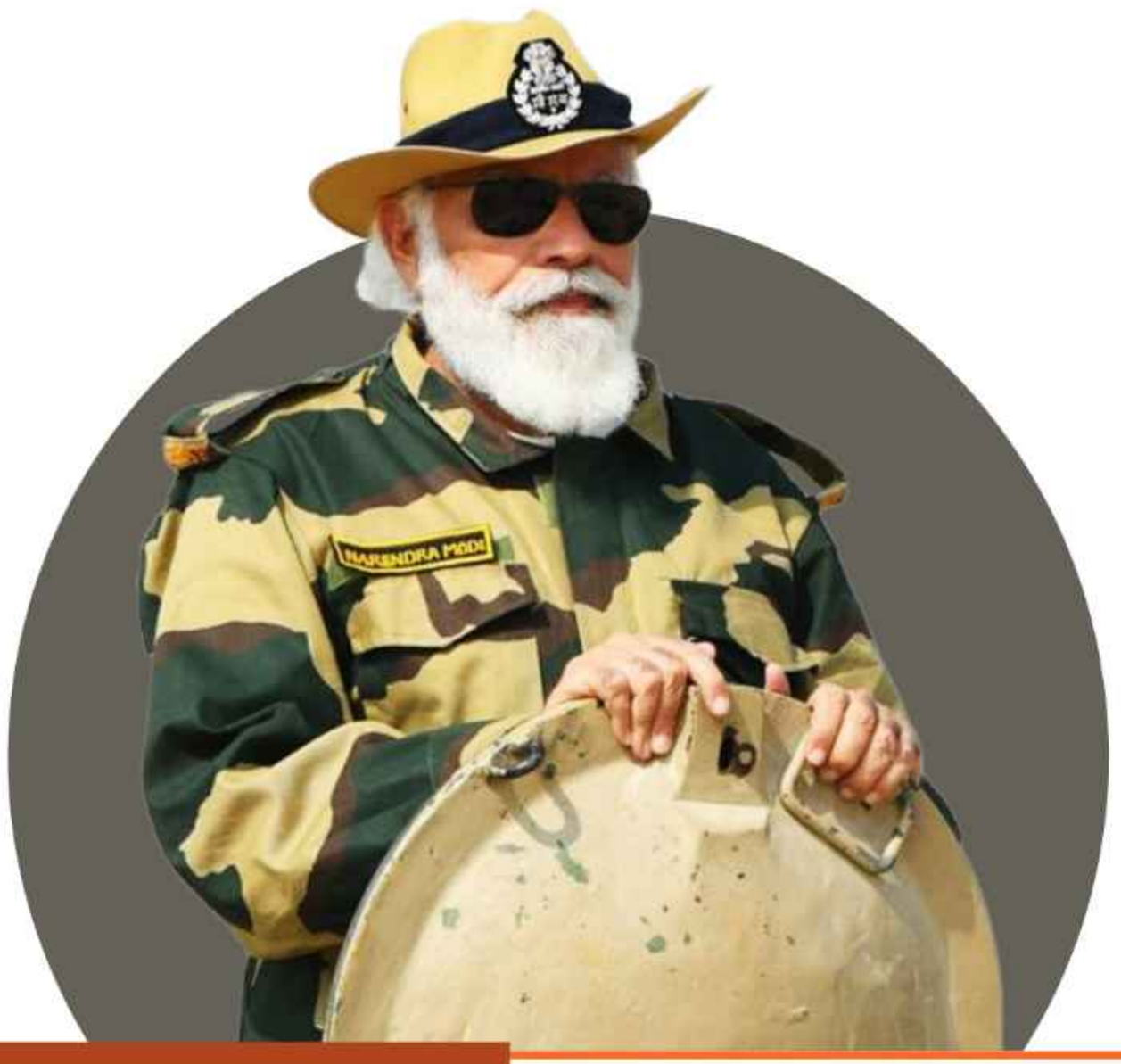

कश्मीर' का मार्ग प्रशस्त करेंगे, ताकि जम्मू और कश्मीर में किसी भी तत्कालिक खतरे को निष्क्रिय किया जा सके। हमारी सतर्कता और शक्ति यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी खतरा अनदेखा या अनियंत्रित न रहे।

- हम सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ करेंगे और आतंकवादी नेटवर्कों को नष्ट करने के लिए सटीक आतंकवाद विरोधी अभियानों का संचालन करेंगे। जम्मू और कश्मीर के एक-एक इंच हिस्से की सुरक्षा के प्रति हमारी अटल प्रतिबद्धता से आतंकवाद का सम्पूर्ण -उन्मूलन विनाश सुनिश्चित किया जाएगा।

- हम सभी समुदायों के साथ गहराई से जुड़ेंगे और सभी के लिए स्थिर और सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए सख्त कानूनी और प्रशासनिक उपाय लागू करेंगे।

- हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी ग्राम रक्षा गार्डों (VDG) को उनका उचित मानदेय मिले, मौजूदा मानदेय को बढ़ाया जाए, उन्हें स्वचालित हथियारों से लैस किया जाए और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई को मजबूत करने के लिए उनकी सेवा शर्तों को संहिताबद्ध किया जाए।

- हम आतंकवाद से लड़ने में जम्मू-कश्मीर पुलिस में SPOs द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हैं और उनके सामने आने वाली समस्याओं से अवगत हैं। हम इनकी समस्याओं का समग्र रूप से समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

- हम पिछले 30 वर्षों से क्षेत्र में आतंकवाद का मुकाबला करने में जम्मू-कश्मीर पुलिस के प्रयासों को मान्यता देते हुए, पुलिस के सभी रैंकों के लिए मासिक जोखिम भत्ता (एमआरए) को सेना/अर्धसैनिक बलों की रैंकों के बराबर करेंगे।

- हम जम्मू-कश्मीर में सीमावर्ती निवासियों के विकास और उत्थान के लिए व्यापक कदम उठाएंगे, जिसमें आवागमन, आजीविका में सुधार लाने, सीमा पार भूमि स्वामित्व से जुड़े मुद्दों को सुलझाने और सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

- हम सीमा पर तनाव के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक बंकरों और परिवार बंकरों की संख्या बढ़ाएंगे। और यह सुनिश्चित करेंगे कि सीमा पार से गोलाबारी नगण्य रहे और संभावित सुरक्षा खतरों के बारे में निवासियों को सचेत करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करेंगे।

युवा सशक्तिकरण और खेल विकास

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने जम्मू-कश्मीर के युवाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किये हैं। मुमकिन योजना के माध्यम से 5,000 युवाओं को व्यावसायिक वाहन खरीदने के लिए पूर्ण धनराशि सहायता की गई है, वहीं 4,000 युवा महिलाओं को उद्यमता हेतु तेजस्विनी योजना के माध्यम से ₹5 लाख तक की सहायता प्रदान की गई है। परवाज़ योजना के माध्यम से लोक सेवा परीक्षा आकांक्षियों को नि:शुल्क अनुशिक्षण प्रदान की गई है।

इसके साथ ही 8,000 अन्य छात्रों को बीएफएसआई क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, और 5,100 युवा संगठनों की स्थापना की गई है।

भाजपा यह सुनिश्चित करेगी कि:

- पंडित प्रेम नाथ डोगरा रोजगार योजना (PPNDRY) के माध्यम से हम जम्मू और कश्मीर में 5 लाख रोज़गार के अवसर पैदा करेंगे।
- हम 'प्रगति शिक्षा योजना' के अंतर्गत कॉलेज के विद्यार्थियों को यातायात-संबंधी भत्ते के रूप में डीबीटी के माध्यम से प्रति वर्ष ₹3,000 प्रदान करेंगे।
- हम सत्ता में आने के 180 दिनों के भीतर सभी सरकारी रिक्त पदों की भर्ती शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- हम अग्निवीरों को जम्मू-कश्मीर की सरकारी नौकरियों और पुलिस भर्ती में 20% कोटा देंगे, और सामान्य कोटे पर कोई प्रभाव डाले बिना जम्मू-कश्मीर की आरक्षण नीति का पालन करेंगे।
- हम एक संपन्न स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेंगे जो युवा उद्यमियों को वित्त, सलाह और इन्क्यूबेशन सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उद्यमिता, नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही हम महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग समुदायों द्वारा स्थापित स्टार्टअप्स को ब्याज अनुदान भी प्रदान करेंगे।

- हम विकास को गति देने वाला व्यावसायिक वातावरण बनाकर जम्मू-कश्मीर में निजी निवेश को आकर्षित करेंगे। हम पर्यटन, आईटी, उत्पादन और कृषि आधारित उद्योगों जैसे प्रमुख क्षेत्रों की क्षमता को लक्षित प्रोत्साहन प्रदान करके, नियमों को सरल बनाकर और बुनियादी ढांचे को उन्नत करके हजारों नौकरियों का सृजन करेंगे।

- हम जम्मू-कश्मीर में नई सरकारी परियोजनाओं और मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देंगे। हम युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए वैश्विक बाजार सेवाओं के लिए स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण भी प्रदान करेंगे।

- हम ऐसे कार्यक्रम और पहल शुरू करेंगे जो जम्मू और कश्मीर के युवाओं को प्रतियोगिताओं, इंटर्नशिप और नौकरी मेलों के माध्यम से शिक्षा और करियर के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर का अनुभव प्रदान करें।

- हम उत्तरी जम्मू और कश्मीर में एक विश्व स्तरीय क्रिकेट अकादमी की स्थापना करेंगे, जिससे यह क्षेत्र क्रिकेट का केंद्र बने।

- हम संपूर्ण क्षेत्र में खेलों में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए जम्मू और कश्मीर में 5 बहुउद्देशीय स्टेडियमों का निर्माण करेंगे।

- हम जम्मू शहर में भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) परिसर की स्थापना करेंगे।

- हम 'दीन दयाल उपाध्याय आयुष वेलनेस एंड डी-एडिक्शन सेंटर्स' की स्थापना करेंगे जो युवाओं को नशा मुक्ति, योग और वेलनेस सुविधाएं के साथ-साथ कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

- हम खेलो इंडिया और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS) के सहयोग से जम्मू-कश्मीर में शीतकालीन खेलों का विकास करेंगे, इसके लिए हम:

  - गुलमर्ग, श्रीनगर, पाडर, डोडा, सरथल (बनी) और अन्य स्थानों पर स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और आइस स्केटिंग जैसी बर्फ आधारित खेलों को बढ़ावा देने के लिए "शीतकालीन पर्यटन विकास कार्यक्रम" (Winter Tourism Development Program) शुरू करेंगे
  - स्थानीय एथलीटों को उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम, गुणवत्तापूर्ण उपकरण और विशेषज्ञ कोचिंग प्रदान करेंगे जिससे जमीनी स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक प्रतिभा को बढ़ावा मिलेगा
  - राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन करेंगे जिससे पर्यटक आकर्षित होंगे और क्षेत्र को शीतकालीन खेल केंद्र में बदला जा सकेगा।

नारी शक्ति- महिलाओं का सशक्तिकरण और उनके अधिकारों की रक्षा

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के महिला-केंद्रित विकास प्रयासों के कारण जम्मू-कश्मीर में महिलाओं की सुरक्षा और उनकी अधिकारिकता में सुधार आया है। लाडली बेटी योजना के माध्यम से 1.61 लाख महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है। जम्मू-कश्मीर में 70,875 महिलाओं को विवाह सहायता प्रदान की गई है और 4.12 लाख से अधिक गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभ पहुंचाया गया है।

भाजपा यह सुनिश्चित करेगी कि:

- 'माँ सम्मान योजना' के कार्यान्वयन के माध्यम से हम जम्मू और कश्मीर के हर घर की सबसे वरिष्ठ महिला को प्रति वर्ष ₹ 18,000 प्रदान करेंगे।
- महिला स्वयं सहायता समूहों के बैंक ऋण पर ब्याज के विषय पर राज्य सरकार सहायता करेगी।
- हम उज्ज्वला लाभार्थियों को हर साल 2 मुफ्त एल.पी.जी सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे।
- हम लाडली बेटी योजना के तहत सहायता राशि में वृद्धि करेंगे, जिससे लड़कियों की शिक्षा और कल्याण सुनिश्चित हो सके, और इसके माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देकर उन्हें सशक्त बनाया जा सके।
- हम पंचायती राज संस्थानों (PRI), शहरी स्थानीय निकाय (ULB) और जिला विकास परिषद (DDC) में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू करेंगे और स्थानीय प्रशासन में उनकी प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु उन्हें नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।
- हम महिलाओं के लिए SDPO स्तर पर एक विशेष महिला पुलिस सेल का गठन करेंगे और महिला पुलिस स्टाफ में वृद्धि करेंगे जिस से महिलाएं बिना किसी डर के अपराधों को रिपोर्ट कर सकें। हम महिला पुलिस अधिकारियों को उनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशीलता और

प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान करेंगे।

- हमारा लक्ष्य जम्मू-कश्मीर में 50,000 लखपति दीदी बनाना है। इसके लिए हम महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को ऋण तक पहुंच, वित्तीय प्रबंधन में प्रशिक्षण और सुदृढ़ बाजार संपर्क प्रदान कर सशक्त और विस्तारित करेंगे।

- हम स्वयं सहायता समूहों की सहयोगात्मक भागीदारी के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को ताजा और पौष्टिक नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए बाइटस योजना (सशक्त स्वं-सहयता समूहों के माध्यम से नाश्ते की पहल) शुरू करेंगे।

- हम स्थानीय आर्थिक गतिविधियों, जैसे हस्तशिल्प, कृषि और पर्यटन के साथ जुड़े हुए लक्षित कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करेंगे। ये कार्यक्रम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यमशीलता कौशल के निर्माण पर केंद्रित रहेंगे।

- हम ऋण आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाकर और कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराकर महिला उद्यमियों के लिए माइक्रो फाइनेंस तक पहुंच में सुधार करेंगे, साथ ही जम्मू-कश्मीर में उद्यमिता कार्यक्रमों और स्टार्ट-अप इनक्यूबेटरों के माध्यम से मार्गदर्शन, नेटवर्किंग के अवसर और वित्तीय सहायता भी प्रदान करेंगे।

- हम लड़कियों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अवसरों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बालिका शिक्षा अभियान सहित व्यापक शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम शुरू करेंगे।

- हम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रमों का विस्तार करेंगे, विशेष रूप से स्टेम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) जैसे कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों में।

- हम महिलाओं को, विशेषकर घरेलू हिंसा, दहेज और उत्तराधिकार विवादों के मामलों में, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिले में कानूनी सेवा केंद्र स्थापित करेंगे।

- हम विशिष्ट लिंग विविधता लक्ष्यों (Specific Gender Diversity Targets) को पूरा करने वाले संगठनों को कर प्रोत्साहन और अन्य लाभ प्रदान करके निजी क्षेत्र की कंपनियों को अधिक महिलाओं को नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

- हम महिलाओं को कानून के तहत उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए कानूनी साक्षरता अभियान चलाएंगे, जिसमें संपत्ति अधिकार, उत्तराधिकार कानून और घरेलू हिंसा आदि से सुरक्षा शामिल हैं।

- हम नीतियों और कार्यक्रमों पर सार्वजनिक परामर्श में महिलाओं को सक्रिय रूप से शामिल करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनके दृष्टिकोण और आवश्यकताओं पर विचार किया जाए।

कृषि, किसान कल्याण और पशुपालन

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में एनडीए सरकार कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण को लेकर प्रतिबद्ध है, जिसमें बागवानी और पुष्पखेती पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में हमने अनेक उपलब्धियाँ प्राप्त की, जिसमें सब्जियों, तिलहन और मशरूम की उपज दुगनी, और ट्राउट का उत्पादन तीन गुणा बढ़ गया है।

भाजपा यह सुनिश्चित करेगी कि:

- हम जम्मू और कश्मीर के किसानों की उन्नति सुनिश्चित करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मौजूदा ₹ 6,000 के अतिरिक्त ₹ 4,000 प्रदान करेंगे, जिससे कुल राशि ₹ 10,000 हो जाएगी।

- हम कृषि गतिविधियों के लिए बिजली की दरों को 50% तक कम कर देंगे, जिससे किसानों के लिए सिंचाई पंप और अन्य मशीनरी संचालित करना आसान हो जाएगा।

- हम अपने किसानों की उचित आय सुनिश्चित करने के लिए गेहूं, चावल, मक्का, दालें और अन्य कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सुनिश्चित करेंगे।

- हम सफल हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम (HPMC) की तर्ज पर जम्मू और कश्मीर में बागवानी उत्पाद प्रसंस्करण और विपणन सहकारी को बढ़ाएंगे, जो स्थानीय किसानों को सशक्त बनाएगा, उनकी आय में वृद्धि करेगा और बागवानी उद्योग का विकास सुनिश्चित करेगा।

- हम जम्मू-कश्मीर में आधुनिक तकनीकों और स्मार्ट मार्केटिंग का उपयोग करते हुए बागवानी, विदेशी फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन, मछली पालन और एकीकृत खेती सहित विविध कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देंगे।

- हम उन्नत खेती और कीट नियंत्रण विधियों को नियोजित करते हुए सेब, केसर, अखरोट, बादाम और कंडी-विशिष्ट फलों जैसे लीची, आम और ड्रैगन फ्रूट जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती पर ध्यान केंद्रित करेंगे और इनकी निर्यात क्षमता को बढ़ाएंगे।

- हम कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं का विकास करेंगे, ग्रामीण मंडियों के माध्यम से बाजार संपर्क के लिए सुविधाएं प्रदान करेंगे, और जम्मू-कश्मीर के कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए निर्यात बाजारों का समर्थन करेंगे।

- हम कृषि उपकरणों और उर्वरकों के लिए सब्सिडी बढ़ाएंगे जिससे किसानों के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित होगी।

- हम जम्मू के कंडी क्षेत्र में खैर के पेड़ों को बेचने के संबंध में गरीब किसानों के सामने आने वाली समस्याओं को व्यापक रूप से संबोधित करेंगे, जिसमें हम समय सीमा की कठोरता और 10 साल के कटाई कार्यक्रमों में अधिक गांवों को शामिल करेंगे।

- हम प्रमाणीकरण सहायता, जैविक इनपुट और जैविक कृषि पद्धतियों में प्रशिक्षण प्रदान करके, विशेष रूप से उच्च निर्यात क्षमता वाली फसलों के लिए जैविक खेती को बढ़ाएंगे।

- हम ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए और किसानों को उन्हें अपनाने के लिए सब्सिडी प्रदान करके सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण करेंगे।

- हम ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करेंगे जो प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाते हुए किसानों को मौसम, बाजार की कीमतों और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाएँगे।

- हम एआई-आधारित फसल निगरानी, आपूर्ति श्रृंखला पारदर्शिता के लिए ब्लॉकचेन और आईओटी-आधारित स्मार्ट खेती समाधान जैसे नवाचारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्षेत्र में कृषि-तकनीक स्टार्टअप की स्थापना को बढ़ावा देंगे।

- हम किसानों को कम ब्याज दरों पर ऋण तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करेंगे, साथ ही छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों में निवेश करने के लिए विशेष ऋण योजनाएं प्रदान करेंगे।

- हम संगठित मोल-भाव बढ़ाने और उचित मूल्यों को सुनिश्चित करने के लिए किसान सहकारी समितियों की स्थापना करेंगे, तथा पैकेजिंग, ब्रांडिंग और गुणवत्ता नियंत्रण सहित मूल्य संवर्धन के लिए प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करेंगे।

- हम उच्च निर्यात क्षमता वाली फसलों की पहचान कर उन्हें वैश्विक बाजार में बढ़ावा देने के लिए रणनीति विकसित करेंगे।

- हम जम्मू-कश्मीर में किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) की संख्या बढ़ाकर 600 करने, कृषि सहयोग को मजबूत करने और किसानों को समग्र समर्थन प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेंगे।

- हम स्थानीय कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और मूल्य वर्धित उत्पादों का निर्माण करने के लिए पुंछ, राजौरी, डोडा, बारामूला और बडगाम में मांस और दूध प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करेंगे।

- हम कश्मीरी सेबों के लिए जीआई (GI) टैग प्राप्त करके स्थानीय सेब उत्पादकों को आयातित सेबों के प्रभाव से बचाने के लिए कड़े कदम उठाएंगे।

- राष्ट्रीय केसर मिशन के माध्यम से, हम केसर की उपज और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सटीक कृषि जैसी आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देंगे। हम कश्मीरी केसर को दुनिया भर में अनोखे तरीके से बेचने के लिए हाल ही में प्राप्त जीआई टैग का लाभ उठाएंगे, और किश्तवाड़ी केसर को खास बढ़ावा देंगे। हम सीमेंट कारखानों से निकलने वाली धूल और कृंतक संक्रमण जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों का भी समाधान करेंगे।

गरीब कल्याण- सशक्त और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण

अनुछेद 370 के हटने के बाद एनडीए सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि जम्मू-कश्मीर विकास और सशक्तिकरण के पथ पर आगे बढ़े। इसके लिए यहाँ 890 केंद्रीय कानून लागू किये गए, 205 पुराने और पुराने राज्य कानूनों को निरस्त किये, और 130 राज्य कानूनों को संशोधित किया गया, जिससे एक समान कानून प्रणाली की स्थापना हुई जो सब नागरिकों को सुरक्षा और शक्ति प्रदान करता है। हमने सरकारी पदों को भरा है और आरक्षण नीतियों में वृद्धि की, जिससे उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके और सबको उनके अधिकार मिल सकें।

भाजपा यह सुनिश्चित करेगी कि:

- हम 'हर घर नल से जल' के माध्यम से सभी को पेयजल उपलब्ध कराएंगे।
- हम प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से परिवारों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएंगे, जिसमें सौर उपकरण की स्थापना के लिए ₹10,000 की सब्सिडी भी दी जाएगी।
- हम सभी उपभोक्ताओं के लिए बिजली और पानी के बकाया बिलों के लिए एक समाधान योजना लाएंगे।
- हम वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता पेंशन को ₹1,000 से तीन-गुना बढ़ाकर ₹3,000 करेंगे, जिससे कमजोर वर्गों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित हो सके।
- हम अटल आवास योजना के माध्यम से भूमिहीन लाभार्थियों के लिए 5 मरला ज़मीन का मुफ्त आवंटन सुनिश्चित करेंगे।
- हम सभी की खाद्य सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं; पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ, हम जम्मू-कश्मीर के प्रत्येक बीपीएल परिवार को 5 किलो मुफ्त चावल और 1 किलो मुफ्त चीनी प्रदान करेंगे।

- हम नीतिबद्ध तरीके से प्राथमिकता के आधार पर विस्थापित लोगों के पुनर्वास सुनिश्चित करेंगे।

- हम जम्मू-कश्मीर में न्यूनतम वेतन दर बढ़ाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि श्रमिकों को विभिन्न श्रम कानूनों का पूरा लाभ मिले। हम सभी दैनिक वेतनभोगी और संविदाकर्मियों के लिए उचित वेतन, नौकरी की सुरक्षा, बुनियादी सुविधाएँ एवं उचित कार्य घंटों के साथ सुरक्षित कार्य स्थल का अधिकार सुनिश्चित करेंगे।

- हम जम्मू-कश्मीर के प्रत्येक निवासी को मुफ्त व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए श्री महाराजा हरि सिंह बीमा योजना (SMHSBY) की शुरुआत करेंगे।

- हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आवास नीतियां कम आय वाले परिवारों, एकल महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों जैसे कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देकर समावेशी हों।

- हम गरीब लड़कियों के परिवारों को विवाह संबंधी खर्च वहन करने में सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य विवाह सहायता योजना (SMAS) के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता को दोगुना करेंगे।

- हम राशन कार्डों के विभाजन से संबंधित समस्याओं का समाधान करेंगे और परिवार के वर्तमान स्थिति को सही ढंग से दर्शाने वाले परिवार राशन कार्डों का पुनर्निर्माण सुनिश्चित करेंगे।

- हम सभी निवासियों के लिए एक समग्र जीवन अनुभव सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और सार्वजनिक परिवहन जैसी एकीकृत सामुदायिक सेवाओं के साथ आवासीय कॉलोनियों का विकास करेंगे।

- हम ग्रामीण आवास को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। इसके साथ ही, हम कॉलोनियों को नियमित करने के लिए नीतियों को लागू करेंगे, जिससे उन्हें कानूनी ढांचे में लाया जा सके और संपत्ति के अधिकार, बुनियादी ढांचा और आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें।

- हम नगरपालिकाओं की सीमा में संरक्षक घरों के निवासियों को स्वामित्व अधिकार सुनिश्चित करेंगे। यह हमारी प्रतिबद्धता है तथा इसका समाधान सामाजिक स्थिरता और इन क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करेगा।

- हम अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद अधिकार प्राप्त शरणार्थियों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करेंगे। इसमें उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना, आवश्यक सेवाओं तक उनकी पहुँच को सुधारना और समाज में उनकी

एकीकरण प्रक्रिया को सुगम बनाना शामिल है। इसके साथ ही, हम उन्हें संपत्ति के अधिकार, आवास और रोजगार से संबंधित कानूनी मुद्दों में भी सहायता प्रदान करेंगे।

- हम एक पारदर्शी और निष्पक्ष भूमि अधिग्रहण नीति लागू करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि भूमि दाताओं को विकास परियोजनाओं में उनके योगदान के लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। हम प्रशंसा पत्र के माध्यम से भूमि दाताओं को भी मान्यता देंगे।

- हम जम्मू और कश्मीर में दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय सेवाओं, डिजिटल प्लेटफार्मों और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता देते हुए, सुलभता और समावेशन में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

- हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े मामलों को संभालने के लिए समर्पित फास्ट-ट्रैक अदालतों के साथ एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के कड़े कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेंगे।

- हम पूर्व-सैनिकों को सहयता प्रदान करेंगे, इसके लिए हम:

  - पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए नागरिक जीवन में उनके सुचारू एकीकरण के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू करेंगे
  - सभी जिलों में जिला सैनिक बोर्डों और सैनिक कालोनियों की स्थापना करेंगे
  - शहीद परिवारों को मुफ्त आवासीय भूमि और उनके बच्चों को शीर्ष संस्थानों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करके सम्मानित करेंगे।

संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में ठोस निवेश किया है, जिसमें 3,104 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों सहित 4,000 से अधिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर ₹7,000 करोड़ से अधिक खर्च किए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना जिसको जम्मू-कश्मीर में सेहत-पीएम जय के नाम से लागू की गई है, के माध्यम से 19.02 लाख परिवारों को 251 हस्पतालों में ₹2285 करोड़ की राशि से 12.9 लाख उपचारों की सहायता प्रदान गई है।

भाजपा यह सुनिश्चित करेगी कि:

- हम आयुष्मान भारत सेहत योजना के तहत मौजूदा ₹5 लाख के कवरेज के अतिरिक्त ₹2 लाख प्रदान करेंगे, जिससे सभी के लिए सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही, शेष स्वास्थ्य संस्थानों को भी आयुष्मान भारत सेहत योजना के अंतर्गत जोड़ेंगे, जिससे इससे जुड़ी लालफीताशाही और औपचारिकताओं में कमी आएगी।
- हम जम्मू-कश्मीर में प्रत्येक निवासी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए 100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करेंगे।
- हम डॉक्टरों के कार्य परिस्थितियों को बेहतर बनाएंगे, अस्पताल के बुनियादी ढांचे को दोगुना करेंगे और उन्हें उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक संसाधन सुनिश्चित करेंगे।
- हम सभी जिला और उप-जिला अस्पतालों में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती करेंगे।
- हम जम्मू-कश्मीर के प्रत्येक ब्लॉक में समर्पित मातृ स्वास्थ्य देखभाल केंद्र स्थापित करेंगे, जिससे व्यापक देखभाल सुनिश्चित होगी तथा गर्भवती महिलाओं के लिए मूलभूत सेवाओं की समस्या समाप्त होगी।
- हम इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए एक समग्र अभियान चलाएंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि:
    - सभी पीएचसी (PHC) में क्लीनिकल सुविधाएं हो
    - सभी सीएचसी (CHC) में डायलिसिस/ मोतियाबिंद सेवाएं हो
    - सभी जिला अस्पतालों में आघात/ आपातकालीन (Trauma/Emergency) स्वास्थ्य सुविधाएं हो।
- हम जम्मू-कश्मीर में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित करने के लिए निजी स्वास्थ्य संस्थाओं को प्रोत्साहित करेंगे।
- हम समय-समय पर ब्लॉक स्तर पर योग शिविर आयोजित करके तथा जिला स्तर पर योग प्रशिक्षक तैयार करके समग्र रूप से स्वास्थ्य को बढ़ावा देंगे।

जम्मू-कश्मीर- पर्यटन का मुकुट रत्न

जम्मू-कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता और महान सांस्कृतिक विरासत हमेशा से यहाँ की सबसे विशेष आकर्षण का केंद्र रही है। इसको ध्यान में रखते हुए एनडीए सरकार ने यहां के पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए अथक प्रयास किए हैं, जिसके कारण यह स्थान फिर से एक मुख्य पर्यटन केंद्र बन गया है। केवल 2023-24 में ही श्री अमरनाथ यात्रा के लिए 5.1 लाख और श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए 93 लाख श्रद्धालु यहाँ पहुँचे।

भाजपा इसके विस्तार के लिए यह सुनिश्चित करेगी कि:

- हम जम्मू संभाग में डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी, पुंछ और उधमपुर, कठुआ के ऊपरी इलाकों जैसे स्थानों को उनकी सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और प्राकृतिक सुंदरता पर प्रकाश डालते हुए एक विशिष्ट पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे।

- हम जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर और नियंत्रण रेखा पर बॉर्डर पर्यटन का विस्तार करेंगे।

- हम रिवरफ्रंट परियोजनाओं (जैसे तवी प्रोजेक्ट) को पूरा करेंगे और रिवर राफ्टिंग, वाटरफ्रंट डाइनिंग, वॉकिंग ट्रेल्स और जम्मू-कश्मीर की नदियों के किनारे सांस्कृतिक उत्सवों जैसे सौंदर्य अपील और मनोरंजक अवसरों को बढ़ाने के लिए एक योजना की शुरुआत करेंगे।

- हम कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए:
  - श्रीनगर शहर की डल झील को विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे, और जल क्रीड़ा (Water Sports) को बढ़ावा देंगे
  - श्रीनगर के टटू ग्राउंड में मनोरंजन पार्क स्थापना
  - कश्मीर घाटी में गुलमर्ग और पहलगाम को आधुनिक पर्यटन शहर के रूप में विकसित करेंगे और इसके लिए जरूरी बुनियादी ढांचे को बढ़ाएंगे।

- हम प्रमुख स्थलों के लिए बुनियादी ढांचे और संपर्क को बढ़ाकर विभिन्न पर्यटक परिपथों को विकसित और बढ़ावा देंगे। इनमें से कुछ प्रमुख स्थल हैं:
  - बूढ़ा अमरनाथ, श्री माता वैष्णों देवी, शारदा देवी पीठ, और मचैल माता मंदिर
  - बाबा गुलाम शाह बादशाह, नंगली साहिब पुंछ गुरुद्वारा और बूढ़ा अमरनाथ परिपथ

- सुरीसर, मनसर, सनासर, पटनीटॉप परिपथ
- सोनमर्ग, पहलगाम, मट्टन, मार्तंड परिपथ
- राजौरी पुंछ सर्किट की सात झीलें
- प्रमुख मंदिर, मंदिर, ज़ियारत और अन्य धार्मिक स्थल।

हम भक्तों के अनुभवों को बेहतर बनाने तथा इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए माता सुकराला की छड़ी यात्रा, मणि महेश यात्रा, गंगाबल यात्रा आदि जैसी तीर्थ यात्राओं के लिए सुविधाएं बढ़ाएंगे।

हम मंतलाई, पटनीटॉप, बंगस घाटी, लोलाब घाटी और अन्य स्थलों में विश्व स्तरीय कल्याण पर्यटन (World-class wellness tourism) स्थलों की स्थापना करेंगे। कल्याण पर्यटन में ध्यान, योग के विभिन्न रूपों और जड़ी-बूटियों, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा से जुड़े उपचार जैसी गतिविधियाँ भी शामिल हैं।

हम जम्मू और कश्मीर के अनूठे परिदृश्य, संस्कृति और साहसिक खेल क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए नए पर्यटक आकर्षणों की पहचान करेंगे और उन्हें विकसित करेंगे।

हम व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करेंगे और पर्यटक गाइडों के बीच व्यावसायिकता और आतिथ्य मानकों को बढ़ाने के लिए पर्यटन अकादमियों और होम स्टे की स्थापना करेंगे।

हम रंजीत सागर बांध के लिए एक अलग झील विकास प्राधिकरण बनाएंगे और जम्मू क्षेत्र में झील पर्यटन को बढ़ावा देंगे।

हम जम्मू-कश्मीर में प्राथमिकता वाले पर्यटन स्थलों के लिए अलग विकास प्राधिकरण बनाएंगे, जिसमें राजौरी-पुंछ की सात झीलें, धर महानपुर बसोहली, सियोज धर रामनगर, डुडू बसंतगढ़ उधमपुर और अन्य क्षेत्र, ताकि उनके पर्यटन और आर्थिक विकास क्षमता का पूरी तरह से उपयोग किया जा सकें।

हम जम्मू और श्रीनगर में यात्रा एवं पर्यटन कियोस्क स्थापित करेंगे, जिससे यात्रा आसान होगी, विदेशी मुद्रा का आदान-प्रदान होगा तथा पर्यटकों को निर्बाध अनुभव के लिए व्यापक जानकारी और सहायता मिलेगी।

हम राजौरी-पुंछ से कश्मीर तक प्रमुख मुस्लिम तीर्थस्थलों और मस्जिदों को शामिल करते हुए प्रोजेक्ट सफर शुरू करेंगे, जिसमें बाबा गुलाम शाह बादशाह, चरार-ए-शरीफ, हजरतबल और हजरत शाह असरार, ऐतिहासिक जामिया मस्जिद राजौरी और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण ख्वाजा नक्शबंद साहिब तीर्थ शामिल हैं।

संस्कृति और सभ्यता

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने जम्मू-कश्मीर की संस्कृति और सभ्यता की विरासत को पुनर्जीवित किया है। शारदा और मार्तंड सूर्य मंदिरों जैसे प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार से लेकर कश्मीरी पंडित तीर्थस्थलों की सुरक्षा तक, हमने इस क्षेत्र की समृद्ध विरासत का सम्मान किया है। स्थानीय उत्पादों की जीआई टैगिंग और क्षेत्रीय भाषाओं की मान्यता जैसी पहल जम्मू-कश्मीर के विविध सांस्कृतिक ताने-बाने को संरक्षित और बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

भाजपा आगे निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी:

- हम ऋषि कश्यप तीर्थ पुनरुद्धार अभियान के अंतर्गत हिंदू मंदिरों और धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण करेंगे। हम 100 खंडहर मंदिरों का जीर्णोद्धार करेंगे और मौजूदा मंदिरों का और अधिक विकास करेंगे धार्मिक और आध्यात्मिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी से, जिसमें शंकराचार्य मंदिर (ज्येष्ठेश्वर मंदिर), रघुनाथ मंदिर और मार्तंड सूर्य मंदिर आदि शामिल रहेंगे।

- हम मंदिरों, गुरुद्वारों और दरगाहों की सुरक्षा, परिरक्षण और पुनर्निर्माण के लिए एक समर्पित कानूनी और प्रशासनिक ढांचे को लागू करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाए।

- हम पूज्य गंगा आरती की तर्ज पर जम्मू में तवी नदी पर तवी आरती और कश्मीर में झेलम पर वितस्ता आरती का आयोजन करेंगे।

- हम जम्मू-कश्मीर से विस्थापित बड़ी आबादी वाले शहरों में जम्मू-कश्मीर भवन और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करेंगे।

- हम गोजिरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने, इसके सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखने और प्राथमिक कक्षाओं में पंजाबी और डोगरी को 'वैकल्पिक विषयों' के रूप में बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे।

- हम दार्दी, पहाड़ी, शिना, शिराज़ी, बाल्टी, और शारदा और टांकरी जैसी स्थानीय भाषाओं और संस्कृतियों का संरक्षण सुनिश्चित करेंगे।

- हम प्रमाणिक जानकारी प्रसारित करने और स्थानीय संस्कृतियों को संरक्षित करने के लिए आकाशवाणी और डीडी केंद्र जम्मू को उचित व्यवस्था और उपकरणों के साथ उन्नत करना सुनिश्चित करेंगे।

- हम जम्मू और कश्मीर की समृद्ध खाद्य धरोहर को बढ़ावा देने का वादा करते हैं, इसके लिए हम:
  - जम्मू और कश्मीर फूड स्ट्रीट की स्थापना करेंगे
  - जम्मू में एक और श्रीनगर में एक द्विवार्षिक खाद्य महोत्सव का आयोजन करेंगे
  - डोगरी और कश्मीरी पंडित व्यंजनों सहित पारंपरिक व्यंजनों के दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए रसोइयों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक डोगरी, कश्मीरी, पंजाबी और पहाड़ी खाद्य कला अकादमी का निर्माण करेंगे।

- हम हथकरघा और हस्तशिल्प कारीगरों जैसे बसोहली पश्मीना शॉल उत्पादकों को उत्पादन इकाइयों की स्थापना और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित करेंगे।

- हम पारंपरिक लोक कलाओं और कारीगरों को संरक्षित करने और प्रोत्साहित करने के लिए 'लोक कलाकार कल्याण कोष' का गठन करेंगे।

- हम बसोहली चित्रकला, अखरोट नक्काशी, पेपर-माशी, खटमबंद, और राजौरी चिकरी लकड़ी शिल्प जैसी पारंपरिक कलाओं और शिल्पों के निर्यात और विपणन के लिए एक मंच प्रदान करेंगे।

- हम माता वैष्णो देवी मंदिर में लंबे समय से चले आ रहे बारीदार मुद्दे का न्यायोचित और निष्पक्ष समाधान करेंगे तथा समानता सुनिश्चित करेंगे।

आर्थिक सशक्तिकरण और औद्योगिक विकास

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नई औद्योगिक नीति लागू की गई है और ₹1,26,582 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और ₹6,624 करोड़ के निवेश प्राप्त हुए हैं जिससे 5.5 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा हुआ है। पहली बार, नई औद्योगिक नीति के तहत ₹500 करोड़ से अधिक निवेश इकाइयाँ स्थापित की गई हैं।

भाजपा आगे निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी:

- हम औद्योगिक निवेश को और बढ़ावा देंगे, जो पहले ही ₹60,000 करोड़ तक पहुंच चुका है और लगभग 2 लाख नौकरियां उत्पन्न कर चुका है। हमारा लक्ष्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से इस निवेश और रोजगार सृजन को चार गुना करना है, जिसमें उच्च-विकास वाले उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

- जम्मू शहर में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के रूप में आईटी हब (IT Hub) की स्थापना।

- मौजूदा व्यवसायों और छोटे व्यापारियों को समर्थन देने के लिए निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे:

  - जम्मू-कश्मीर में 7,000 मौजूदा एमएसएमई (MSME) इकाइयों की मौजूदा समस्याओं के समाधान के लिए एक नई नीति तैयार की जाएगी ताकि भूमि और सार्वजनिक उपयोगिताओं तक पहुंच को संबोधित किया जा सके

- वर्तमान बाजारों और वाणिज्यिक स्थानों पर काम कर रहे छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के पट्टा विलेखों (Lease Deeds) के नियमितीकरण से संबंधित मुद्दों को समयबद्ध तरीके से निपटाया जाएगा
- इसके साथ ही इकाइयों और मजदूरों की समस्याओं का निवारण करने के लिए हम कठोर कदम उठाएंगे।

हम सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में भारी उद्योगों की स्थापना के अवसरों की खोज करेंगे, जिससे जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए महत्वपूर्ण निवेश आएगा और उच्च-मूल्य नौकरियों का सृजन होगा। इसके अलावा, हम क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए उधमपुर, कठुआ, सांबा, गांदरबल और बडगाम में औद्योगिक हब स्थापित करेंगे।

हम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट गारंटी योजनाओं के माध्यम से आसान ऋण और अनुदान प्रदान करेंगे।

हम रियासी में लिथियम भंडारों की व्यापक, वैज्ञानिक खोज और पारदर्शी उत्खनन शुरू करेंगे, जिसमें खनन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इससे प्राप्त राजस्व का निवेश बुनियादी ढांचे को उन्नत करने और स्थानीय लोगों को रोज़गार प्रदान करने वाली परियोजनाओं में किया जाएगा।

हम बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में क्षेत्र की स्थिति को मजबूत करने और औद्योगिक विकास का समर्थन करने के लिए एक ईवी उत्पादन गलियारा विकसित करेंगे।

हम जम्मू-कश्मीर के सभी जिलों में व्यापार केंद्र स्थापित करेंगे, जिससे पूरे क्षेत्र में वाणिज्य और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

हम वित्तीय और कानूनी विवादों के समाधान में तेजी लाने के लिए ऋण वसूली (Debt Recovery Tribunal) और आयकर न्यायाधिकरणों (Income Tax Tribunal) सहित समर्पित न्यायाधिकरणों

की स्थापना करेंगे, जिससे व्यापार अनुकूल वातावरण का निर्माण होगा और आर्थिक विकास को तेज़ी मिलेगी।

- हम अपने स्थानीय उद्योगों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और स्वचालन प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए आसान सुविधा प्रदान करेंगे।

- हम औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानीय उद्यमियों को प्राथमिकता देंगे, स्थानीय संसाधनों और प्रतिभा का उपयोग करने वाली इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेंगे, जिससे आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

- हम रोजगार के अवसर पैदा करने और निर्यात को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशों को आकर्षित करने के लिए रणनीतिक रूप से स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) का निर्माण करेंगे।

- हम विशेष रूप से PMAY लाभार्थियों के लिए रेत, पत्थर और बजरी जैसी आवश्यक निर्माण सामग्री की सामर्थ्य और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

- हम निर्माण सामग्री के लिए पारदर्शी मूल्य निर्धारण तंत्र लागू करेंगे, गुणवत्ता नियंत्रण की निगरानी करेंगे, स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को समर्थन देंगे और हरित प्रोत्साहन शुरू करेंगे। निष्पक्षता को और अधिक सुनिश्चित करने के लिए, हम इन सामग्रियों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत तंत्र स्थापित करेंगे।

- हम पारंपरिक कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित करेंगे, 'बेड़ और पेड़' को प्राथमिकता देंगे, तथा स्थानों पर एकीकृत खेती करेंगे:
  - रामबन जिले में अनारदाना गांव
  - किश्तवाड़ जिले के चंढोरा और खरेवा में केसर गांव
  - बडगाम के कनिहामा गांव और बांदीपोरा के क़ाज़ीपुर में ऊन गांव।

- हम जम्मू-कश्मीर की जीआई-टैग वाली वस्तुओं को 'शॉप जम्मू' और 'शॉप कश्मीर' के रूप में ब्रांड करेंगे, ताकि अन्य सभी राज्यों की राजधानियों और सार्वजनिक स्थानों पर दुकानें स्थापित करके उनकी अद्वितीय गुणवत्ता को प्रदर्शित किया जा सके।

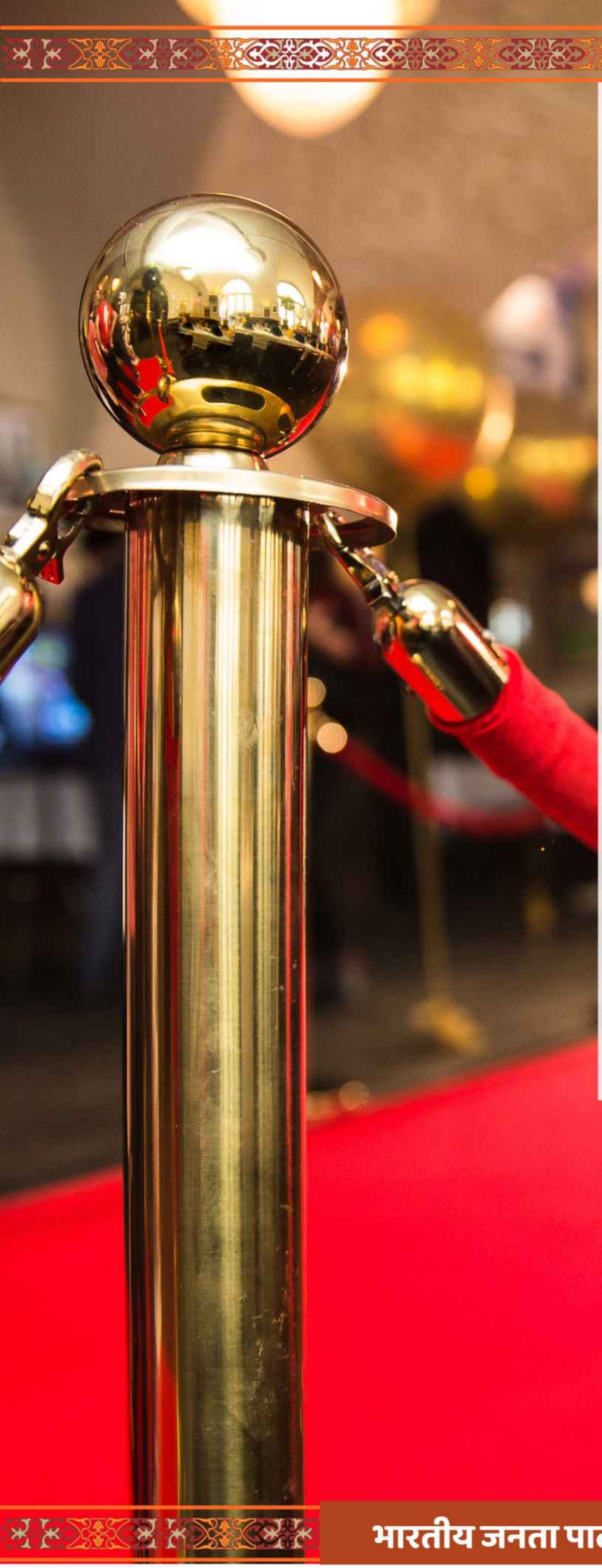

- हम जम्मू और कश्मीर में नई फिल्म नीति 2024 का विस्तार और अपग्रेड करेंगे, इसके लिए हम:
    - लुभावने परिदृश्य, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अद्वितीय अवसरों को प्रदर्शित करने वाले प्रमुख फिल्मांकन स्थानों की पहचान करेंगे और उन्हें बढ़ावा देंगे
    - अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों और व्यापार प्रदर्शनों का आयोजन करेंगे और क्षेत्र को वैश्विक फिल्म निर्माताओं के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करेंगे
    - इन बहुमूल्य स्थानों के निकट अत्याधुनिक फिल्म स्टूडियो और निर्माण सुविधाएं स्थापित करेंगे जिससे फिल्म निर्माताओं को आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जा सके और तार्किक चुनौतियों को न्यूनतम किया जा सके
    - कर छूट, सब्सिडी और अनुदान के माध्यम से फिल्म परियोजनाओं को प्रोत्साहित करेंगें।

शिक्षा और कौशल विकास

2022 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के कार्यान्वयन से यह सुनिश्चित हो गया है कि जम्मू और कश्मीर के स्कूल जाने वाले बच्चों को अब मुफ्त और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सकेगी। एम्स, आईआईटी, आईआईएम और 7 नए मेडिकल कॉलेजों के अलावा, एनडीए सरकार ने 2019 से जम्मू और कश्मीर में 51 नए डिग्री कॉलेज स्थापित किए हैं।

भाजपा आगे निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी:

- हम जम्मू और कश्मीर के युवाओं को JKPSC और UPSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सक्षम बनाएंगे, इसके लिए हम:
  - समय पर साक्षात्कार के साथ निष्पक्ष और न्यायपूर्ण भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे
  - 2 वर्षों के लिए ₹ 10,000 तक की कोचिंग फीस की प्रतिपूर्ति प्रदान करेंगे
  - परीक्षा केन्द्रों तक यातायात-संबंधी लागत और एकमुश्त आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति करेंगे।
- हम दूरदराज के क्षेत्रों में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को टैबलेट/लैपटॉप प्रदान करेंगे।
- हम मौजूदा और आगामी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से 1,000 नई सीटें जोड़ेंगे।
- हम 23,000 से अधिक सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के आधुनिकीकरण में निवेश करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वे नवीनतम तकनीक, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, मुफ्त वाईफाई और संसाधनों से लैस हों।
- 2030 तक प्री-प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल के प्रत्येक बच्चे की बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता हासिल करने के लिए हम 'मिशन प्रवेश' की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत:

- हम सभी 28,178 मौजूदा आंगनवाड़ियों को नई पीढ़ी की 'सक्षम आंगनवाड़ियों' में अपग्रेड करेंगे
- हम सभी योग्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अकादमिक संसाधन व्यक्ति (ARP) बनाने के लिए उनका कौशल उन्नयन करेंगे, जिससे वे प्रीस्कूल छात्रों को पढ़ाने में सक्षम हो सकें।

हम निजी क्षेत्र में स्थानीय कुशल श्रम की मांग को पूरा करने के लिए व्यापक कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करेंगे, जो उद्योग की जरूरतों के अनुरूप होगा तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि युवाओं को स्थानीय और वैश्विक नियोक्ताओं (Global Employers) द्वारा अपेक्षित कौशल प्राप्त हों।

हम अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मौजूदा छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार करेंगे, जिसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक पढाई हो सके।

हम जम्मू-कश्मीर में 10 सरकारी डिग्री कॉलेज खोलेंगे, जिनमें से 4 विशेष रूप से महिलाओं के लिए होंगे।

हम जम्मू-कश्मीर में शिक्षकों के कौशल विकास हेतु कार्यक्रम शुरू करेंगे।

हम विशेष रूप से उच्चतर माध्यमिक और महाविद्यालय स्तर पर लड़कियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, निःशुल्क परिवहन और छात्रावास सुविधाएं प्रदान करेंगे।

हम सभी स्कूलों में तत्काल सुरक्षा ऑडिट कराएंगे, ताकि अपर्याप्त बाड़बंदी, विशेषकर लड़कियों के लिए खराब स्वच्छता जैसी सुरक्षा चिंताओं की पहचान कर उन्हें दूर किया जा सके।

हम विद्यार्थियों को तनाव प्रबंधन (Stress Management), ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद करने के लिए स्कूल पाठ्यक्रम में ध्यान और योग जैसी सचेतनता की प्रथाओं को शामिल करेंगे।

हम मेधावी छात्रों, दिव्यांग छात्रों और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए स्कूल और स्नातक स्तर पर छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे।

हम एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कई क्षेत्रीय आईटीआई और राष्ट्रीय खेल संस्थान (NIS) की तर्ज पर एक खेल संस्थान स्थापित करेंगे।

हम राजौरी-पुंछ क्षेत्र में एक जनजातीय विश्वविद्यालय, और कश्मीर में एक शारदा विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे।

हम स्कुअस्त (SKUAST) विश्वविद्यालय, जम्मू का नाम बदलकर बाबा जित्तो कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रखेंगे तथा इसे केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में अपग्रेड करेंगे, जिससे जम्मू-कश्मीर में युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित होगी।

हम जम्मू-कश्मीर में निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए एक निजी विश्वविद्यालय अधिनियम लागू करेंगे।

सुशासन-
विकास और समृद्धि का शासन

कमियों को दूर करने और विकास में तेजी लाने के लिए, जम्मू-कश्मीर एक व्यापक जिला सुशासन सूचकांक (डीजीजीआई) तैयार करने वाला पहला राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जहां मूल्यांकन किया जाता है और 10 क्षेत्रों और 58 मापदंडों में जिलेवार रैंकिंग प्रकाशित की जाती है। जम्मू-कश्मीर में निष्पादन से पहले और बाद की तस्वीरों के साथ कार्यों के 100% भौतिक सत्यापन और जियो-टैगिंग की एक प्रणाली गठित की गई है।

भाजपा आगे निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी:

- हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, एनएचएम कार्यकर्ताओं, रहबर-ए-खेल कर्मचारियों (ReK), सामुदायिक सूचना केंद्र (CIC) संचालकों, होम गार्ड और राष्ट्रीय युवा कोर (NYC) जैसे महत्वपूर्ण सामुदायिक कार्यकर्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए लक्षित अतिरिक्त सहायता प्रदान करेंगे।

- हम एडहॉक/संविदा/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करेंगे।

- हम पिछले वर्षों के विपरीत स्वतंत्र और निष्पक्ष जनगणना करेंगे, जिससे उचित निर्णय लेने, समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करने तथा कमज़ोर समुदायों के लिए लक्षित हस्तक्षेप सुनिश्चित होगा।

- हम सरकारी कर्मचारियों के लिए सुधार लागू करेंगे जिससे:
  - सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित होगा
  - सभी कर्मचारियों, विशेषकर कश्मीर घाटी में कार्यरत अनुसूचित जाति एवं अन्य कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति बनाई जाएगी।

- हम जम्मू-कश्मीर सरकार के कर्मचारियों के लिए नई एकीकृत पेंशन (UPS) योजना लागू करेंगे, जिसमें सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन की सुविधा होगी।

- हम जम्मू और कश्मीर में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति शुरू करेंगे:
  - जिसमें हम विशेष कार्य बल द्वारा कानून प्रवर्तन और सुरक्षा उपायों को मजबूत करेंगे
  - खुफिया जानकारी साझा करने,

परिचालन समर्थन और क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ निगरानी समन्वय में वृद्धि करेंगे
- कानूनी ढांचे और नीतिगत कार्यान्वयन को मजबूत करेंगे।

हम एक भ्रष्टाचार निरोधक कार्यबल की स्थापना करेंगे तथा भ्रष्टाचार की शिकायतों के निवारण के लिए एक वेब-पोर्टल बनाएंगे, जिसकी निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की जाएगी।

हम निम्नलिखित आयोगों को सुदृढ़/स्थापित करके जम्मू और कश्मीर के कमज़ोर वर्गों के लिए सुरक्षा प्रावधानों से संबंधित सभी मामलों की देखरेख और निगरानी करेंगे:

- महिला आयोग
- अल्पसंख्यक आयोग जिसमें जम्मू-कश्मीर के अल्पसंख्यक जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध शामिल है
- अनुसूचित जाति आयोग
- अनुसूचित जनजाति आयोग
- अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग
- सफाई कर्मचारी आयोग।

हम जिला पुनर्गठन समिति का गठन करेंगे तथा प्रशासनिक सुविधा एवं आवश्यकता के अनुसार जिलों के पुनर्गठन का प्रावधान करेंगे।

हम वकीलों के लिए उचित भवन, कक्ष और सुलह केंद्र सुनिश्चित करेंगे, जिससे उनकी काम करने की स्थिति में सुधार होगा।

हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू-कश्मीर में ब्लॉक स्तर तक प्रत्येक सरकारी कार्यालय पूर्णतः डिजिटल हो।

हम अस्पतालों के बुनियादी ढांचे को दोगुना कर, विशेष रूप से महिला डॉक्टरों और पैरा-मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित कर, और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर, डॉक्टरों की कार्य स्थितियों में सुधार करेंगे।

समय पर न्याय सुनिश्चित करने और कानूनी प्रणाली की समग्र दक्षता में सुधार करने के लिए, हम:

- जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का निवेदन करेंगे
- न्यायाधीशों, मजिस्ट्रेटों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती के माध्यम से जिला और उप-जिला न्यायालयों सहित निचली न्यायपालिका की संख्या को दोगुना करेंगे
- जिला, उप-जिला और मुंसिफ स्तर पर नए न्यायिक परिसरों का निर्माण करेंगे, जिन्हें आधुनिक सुविधाओं और पर्याप्त स्थान से सुसज्जित किया जाएगा, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां इस प्रकार का बुनियादी ढांचा वर्तमान में अनुपलब्ध है।

हम एक एकीकृत सामान्य न्यायाधिकरण परिसर की स्थापना करेंगे जिसमें सभी विशेष अदालतें और न्यायाधिकरण जैसे प्रशासनिक न्यायाधिकरण (Administrative Tribunal), राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (National Company Law Tribunal) आदि होंगे ताकि न्याय तक पहुंच बढ़ाई जा सके, नियमित अदालतों पर बोझ कम किया जा सके और विशेष कानूनी मामलों का विशेषज्ञों द्वारा निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

हम सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार करने की सिफारिश करेंगे और इस पर आगे बढ़ेंगे, जो यहाँ के लोगों पर थोपी गई है और जो जम्मू-कश्मीर के लोगों के खिलाफ की गई नेहरूवादी भूलों में से एक है।

हम जम्मू-कश्मीर में अवैध खनन और गौ-तस्करी के मुद्दों को हल करने के लिए एक विशेष कार्य बल की स्थापना करेंगे।

जम्मू और कश्मीर का निर्माण- बुनियादी ढांचे का विकास और कनेक्टिविटी का विस्तार

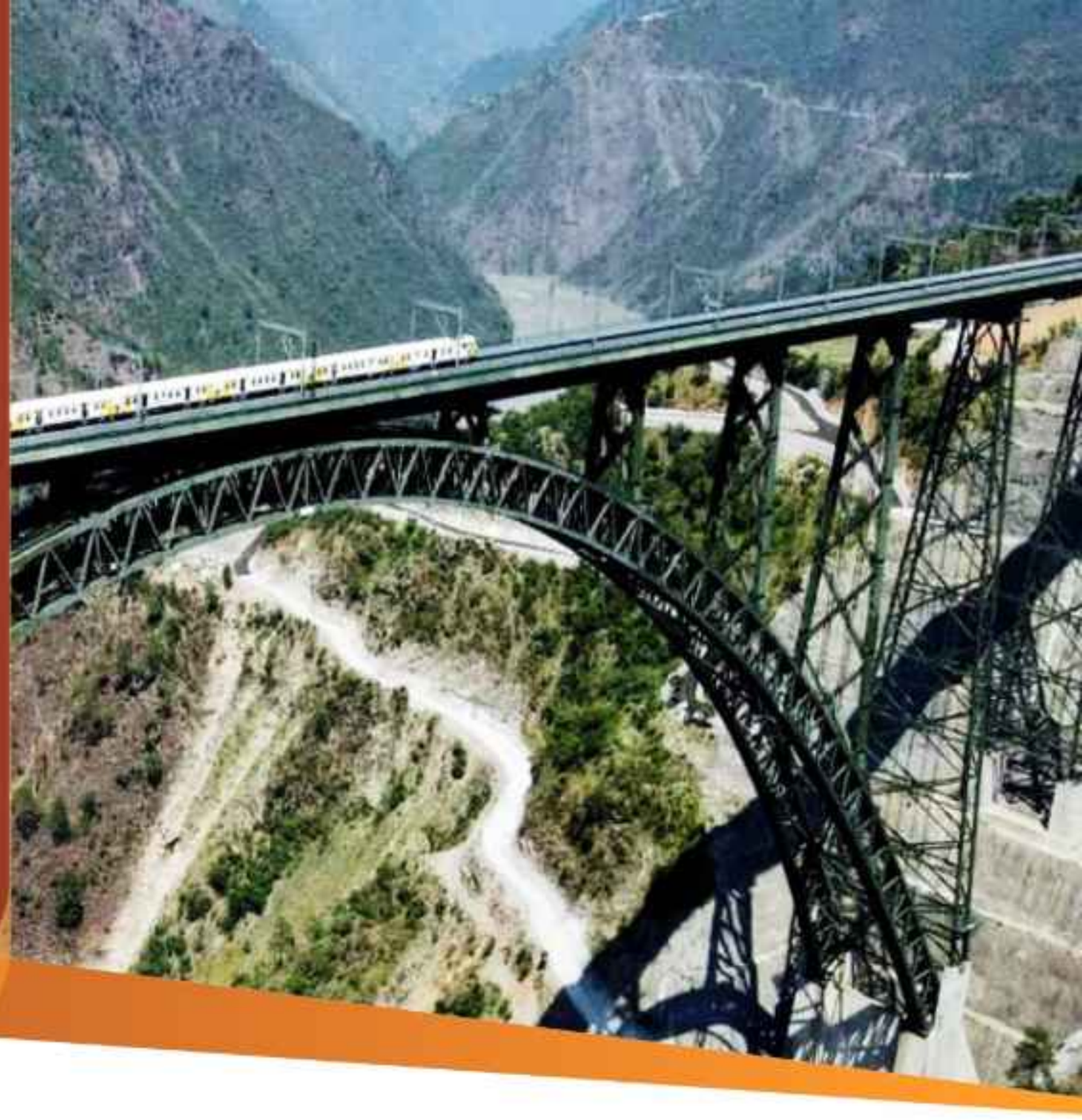

माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में, जम्मू और कश्मीर एक परिवर्तनकारी युग का अनुभव कर रहा है, जो लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों को उल्लेखनीय अवसरों में बदल रहा है। ₹58,477 करोड़ के प्रधान मंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें 53 प्रमुख परियोजनाओं में से 35 को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है।

भाजपा आगे निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी:

- हम जम्मू-कश्मीर में 10,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू-कश्मीर के दुर्गम क्षेत्रों का हर एक गांव सड़क से जुड़े।

- हम 'हर टनल तेज पहल' योजना शुरू करेंगे और जम्मू-कश्मीर में निर्बाध संपर्क के लिए निम्नलिखित सुरंग परियोजनाओं के निर्माण में तेजी लाएंगे:
  - साधना पास सुरंग
  - राज़दान पास सुरंग
  - कटरा-बनिहाल रेलवे सुरंग
  - वैलू-सिघपोरा सुरंग
  - माता बाला सुंदरी सुरंग
  - छत्तरगला सुरंग
  - डेसा-कपरान सुरंग।

- हम संपर्क बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जम्मू में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित करने का आग्रह करेंगे।

- हम जम्मू हवाई अड्डे पर कार्गो हैंडलिंग क्षमता का नवीनीकरण और विस्तार करेंगे।

- हम जम्मू और श्रीनगर शहरों के समग्र बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करेंगे, जिसमें वाणिज्यिक भूमि सहित भूमि उपयोग के लिए एकल खिड़की ऑनलाइन पंजीकरण भी शामिल होगा।

- हम निम्नलिखित रेल परियोजनाओं पर काम में तेजी लाने के लिए रेल मंत्रालय के साथ काम करेंगे:

- बारामूला से उरी और कुपवाड़ा
- जम्मू से राजौरी/पुंछ से शोपियां तक
- उधमपुर-बटोट-किश्तवाड़-डोडा
- मनवाल-बिलावर-महानपुर-बसोहली-दुनेरा-पठानकोट रेलवे लाइन
- चिनाब पुल के पास कौरी गांव में रेलवे स्टेशन का निर्माण संपर्क बढ़ाने के लिए
- सांबा जिले में रेल बुनियादी ढांचे का व्यापक विकास करेंगे।

हम निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास को प्राथमिकता देंगे:

- राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में दयालचक से छलां होते हुए महानपुर तक
- कश्मीर में लखनपुर, महानपुर, बसोली, बानी, भदरवाह, डोडा, किश्तवाड़ और सिंथन टॉप।

हम 'गति शान पुल योजना' शुरू करेंगे और जम्मू-कश्मीर में लोगों और सामान की कुशल आवाजाही के लिए प्रमुख पुल परियोजनाओं के निर्माण में तेजी लाएंगे:

- अजोटे में डबल स्पैन पुल
- गंडबल पुल
- उझ में डबल लेन पुल
- अखनूर में चम्ब पर पुल।

हम शहरी संपर्क में सुधार और गतिशीलता बढ़ाने के लिए जम्मू और श्रीनगर में मेट्रो सेवाएं जल्दी शुरू करेंगे।

हम सम्भाव्य जिलों में सूक्ष्म पनबिजली परियोजनाएं (Micro-hydel Projects) शुरू करके जम्मू-कश्मीर में पनबिजली उत्पादन को 3500 मेगावाट से बढ़ाकर 5000 मेगावाट कर देंगे। इसके अलावा, हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि पनबिजली परियोजनाओं पर लंबित रॉयल्टी का भुगतान समय पर हो जाए।

हम जम्मू-कश्मीर के हर पंचायत केंद्र में वाई-फाई कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेंगे।

हम जम्मू और कश्मीर को "शून्य सड़क दुर्घटना" राज्य बनाने का लक्ष्य रखेंगे, इसमें हम:

- मजबूत सड़क सुरक्षा नीति लागू करेंगे
- त्वरित प्रथम उत्तरदाता कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित करेंगे
- सभी पहाड़ी सड़कों पर क्रैश बैरियर लगाएंगे
- पुलिस चौकियों की संख्या बढ़ाएंगे
- लापरवाही से गाड़ी चलाने पर नजर रखने और रोकने के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर अधिक सीसीटीवी कैमरे और स्पीड रडार लगाए जाएंगे
- प्राथमिक उपचार प्रदान करने और मौतों को कम करने के लिए प्रमुख राजमार्गों और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के साथ मोबाइल चिकित्सा इकाइयों को तैनात करेंगे।

कश्मीरी पंडितों का कल्याण

दशकों से, कश्मीरी पंडित समुदाय न्याय और घरों में सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रहा है। प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने इस लक्ष्य की दिशा में साहसिक कदम उठाए हैं, जिसकी शुरुआत अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, सीमा पार आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने और उनकी वापसी के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने से हुई है।

2014 के बाद से, मोदी सरकार ने कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को सबसे आगे लाया है, पुनर्वास, सरकारी नौकरियां और आवास प्रदान किया है। हम कश्मीरी पंडितों के लिए न्याय और सुरक्षित घर वापसी के लंबे समय से प्रतीक्षित वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

भाजपा आगे निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी:

- कश्मीरी पंडित समुदाय की सुरक्षित वापसी और पुनर्वास में तेजी लाने और उसे सुनिश्चित करने के लिए, हम टीका लाल टपलू विस्थापित समाज पुनर्वास योजना (TLTVSPY) शुरू करेंगे। हम विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय के अधिकारों की रक्षा, संरक्षण और बचाव के लिए उनके प्रतिनिधियों और विस्थापित समुदाय कल्याण बोर्ड से प्राप्त सुझावों को भी शामिल करेंगे।

- हम पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों, पीओजेके शरणार्थियों और वाल्मीकि, गोरखा जैसे आंतरिक रूप से उपेक्षित समुदायों के पुनर्वास में भी तेजी लाएंगे।

- हम कश्मीरी हिंदुओं और सिखों की कठिनाइयों का अध्ययन करने और उनकी चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक जांच आयोग का गठन करेंगे।

- हम प्रधानमंत्री विकास पैकेज के अंतर्गत भर्ती किए गए कर्मचारियों की चिंताओं का समाधान करेंगे, जिसमें निष्पक्ष स्थानांतरण और पदोन्नति नीति का क्रियान्वयन भी शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें वह समर्थन और अवसर मिले जिसके वे हकदार हैं।

- हम विस्थापित कश्मीरी पंडितों के नगरपालिका वोटों को उनके विधानसभा और संसदीय वोटों से अलग करने के तरीकों का अध्ययन करेंगे, जिससे वे स्थानीय चुनावों में भाग ले सकें जहां वे वर्तमान में रहते हैं।

- हम कश्मीर में शुरू से रह रहे हिंदुओं, सिखों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, संरक्षण और सहायता बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे।

- कश्मीर से बाहर जबरन अस्थायी प्रवास के दौरान विस्थापित कश्मीरी हिंदू और सिख समुदायों का सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए, पीड़ित वर्ग को मासिक नकद के रूप में दिए जाने वाले मासिक निर्वाह को उचित रूप से बढ़ाया जाएगा।

- हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू संभाग के विस्थापित लोगों को वे सभी उचित लाभ, सुरक्षा और संरक्षण प्राप्त हों जो कश्मीरी विस्थापितों को मिलती हैं।

पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन

एनडीए सरकार ने वन संरक्षण पर बड़ा जोर दिया है और जम्मू-कश्मीर के लगभग 80% वन सीमांकन रिकॉर्ड को डिजिटलीकृत किया गया है। इसके अलावा, 41,120 कनाल अतिक्रमित भूमि को साफ़ कर दिया गया है। हर गांव हरियाली कार्यक्रम के माध्यम से, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर वन अधिकारियों, पीआरआई और स्थानीय लोगों के सामूहिक वृक्षारोपण प्रयासों के लिए जम्मू और कश्मीर के 4,290 ग्राम पंचायतों, 80 यूएलबी और 6,850 गांवों को कवर किया गया था। इसने वन और वृक्ष आवरण में उल्लेखनीय शुद्ध वृद्धि के साथ जम्मू-कश्मीर को शीर्ष 10 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में स्थान दिया है।

भाजपा आगे निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी:

- हम सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को शामिल करके आवास परियोजनाओं में स्मार्ट टेक्नोलॉजी को लागू करेंगे, जिससे टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल रहने का वातावरण तैयार होगा।

- हम प्रभावी जल प्रबंधन के लिए जलाशयों, नहरों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण और प्रबंधन के साथ-साथ व्यापक वर्षा जल संग्रह प्रणालियों को विकसित और प्रोत्साहित करेंगे।

- हम जम्मू-कश्मीर की समृद्ध जैव विविधता का लाभ उठाते हुए औषधीय और हर्बल पौधों की खेती और प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करेंगे। इस पहल का उद्देश्य नए उद्योग बनाना, आय पैदा करना और हमारी प्राकृतिक विरासत का संरक्षण करना है।

- हम जम्मू-कश्मीर की विशाल पवन ऊर्जा क्षमता का लाभ उठाते हुए उसके उपयुक्त क्षेत्रों में पवन ऊर्जा फार्म विकसित करेंगे।

- हम जम्मू और कश्मीर में झीलों का कायाकल्प करने के लिए अमृत सरोवर मिशन का विस्तार करेंगे और सिंचाई बढ़ाने के लिए उनके चारों ओर नहरों का निर्माण करेंगे।

- हम वन संरक्षण योजना तैयार करेंगे और सभी जिलों के लिए वन विकास और संरक्षण के लिए एक विकेंद्रीकृत कार्य योजना तैयार करेंगे।

- हम जम्मू-कश्मीर में वन्यजीवों के संरक्षण का वादा करते हैं, इसके लिए हम:
  - उन्नत अनुसंधान के साथ जम्मू और कश्मीर में वन्यजीव संरक्षण को बढ़ाएंगे और अवैध शिकार विरोधी उपायों को मजबूत करेंगे,
  - मानव-वन्यजीव संपर्क को कम करने के लिए विशेष वन्यजीव गलियारों का निर्माण करेंगे।

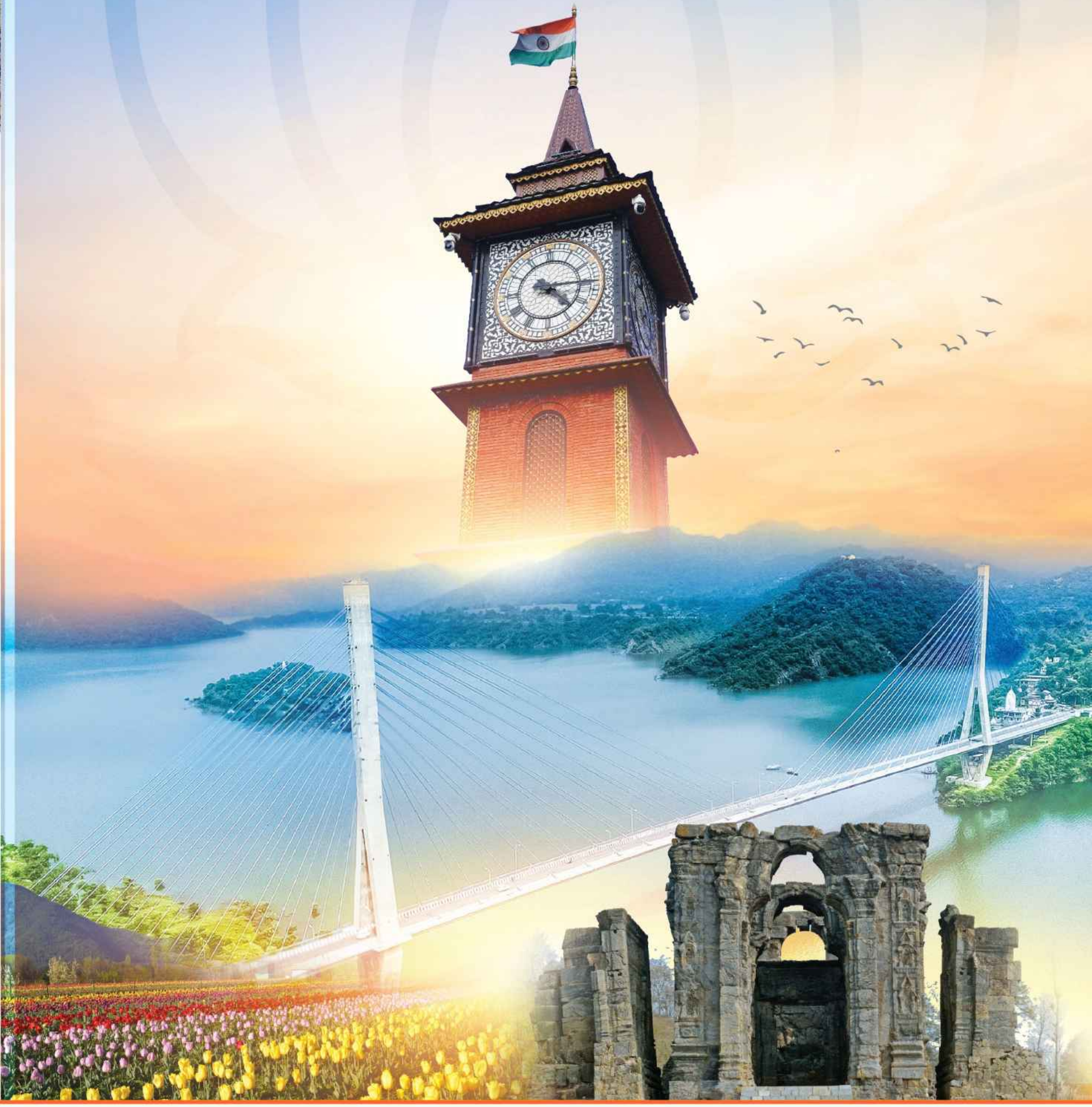

नोट्स

नोट्स

भारतीय जनता पार्टी

जम्मू-कश्मीर

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन,
सेक्टर - 3 एक्सटेंशन, त्रिकुटा नगर, जम्मू
0191 2477230, 231, 629, 771

शांति, स्थिरता और विकास

जम्मू-कश्मीर को मोदी पर विश्वास

Printed at CK Printers # 7006118084 - Qty. - 200 pcs

कमल का बटन दबाएं • भाजपा को जिताएं